V.V. NEWS

वर्ष-13
अंक-28
मूल्य-3
पृष्ठ-4
जौनपुर
11 जुलाई, 2022
सोमवार

सब पर नजर हर खबर पर नजर

वैशवारा

रा. हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

RNI No. UPHIN/3924/2009
डाक पंजीयन जी आजमगढ़/एन.पी./119/15-16

दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, लखनऊ, जौनपुर से एक साथ प्रकाशित

जापान के पूर्व पीएम आबे की हत्या

– जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर शुक्रवार सुबह हमला हुआ था। इस दौरान हमलावर ने उन्हें गोली मारी थी। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली।

टोक्यो। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर शुक्रवार सुबह हमला हुआ था। इस दौरान हमलावर ने उन्हें गोली मारी थी। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। दरअसल, शिंजो आबे संसद के ऊपरी सदन के लिए रविवार को होने वाली वोटिंग के मद्देनजर एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए नारा गए हुए थे। इसी बीच जब वो भाषण दे रहे थे तभी गोली चलने की आवाज सुनी गई।

पकड़ा गया संदिग्ध

पुलिस ने 41 वर्षीय एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। उसका नाम यामागामी तेत्सुया बताया जा रहा है, जिसके पास से एक बंदूक बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि दो गोलियां चलाई गई थीं। इस हमले के बाद पुलिस सतर्क हो गई और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

लंबे समय तक थे पीएम

शिंजो आबे साल 2006 में पहली बार जापान के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि 2007 में बीमारी के चलते उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने 2012 में एक बार फिर से जापान के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और साल 2020 तक इस पद पर रहे।

आपको बता दें कि शिंजो आबे ने 2020 में स्वास्थ्य का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि उनकी एक पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है। उन्होंने कहा था कि अपने कई लक्ष्यों को अधूरा छोड़ना उनके लिए परेशान करने वाली बात है। उन्होंने सालों पहले उत्तर कोरिया द्वारा अगवा किए गए जापानी नागरिकों के मुद्दे, रूस के साथ क्षेत्रीय विवाद और जापान के युद्ध त्यागने वाले संविधान के संशोधन के मुद्दों को हल करने में अपनी नाकामी की बात की थी।

पीएम मोदी ने जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र शिंजो आबे के निधन की खबर से स्तब्ध हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के निधन पर स्तब्ध और दुखी हूं।

हमलावर मौके पर ही गिरफ्तार

आबे की हत्या पर उठे सवाल

- घटना के वक्त पूर्व पीएम के करीब कैसे पहुंचा आरोपी?
- एंबुलेंस आने में 15 मिनट क्यों लग गया?
- जापान से पहले चीनी मीडिया ने कैसे ब्रेक की खबर?

इलेक्शन कैंपेन में पूर्व सैनिक ने पीछे से गोली मारी, 6 घंटे बाद निधन

मिशन 2024 की जमीनी रणनीति तैयार करने में लगी भाजपा

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2017 से प्रारंभ हुआ जीत का सिलसिला और आगे तक बरकरार रखने की योजना तैयार करने में लगी है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में सम्पन्न बैठक में जमीनी रणनीति का प्रारूप तैयार किया गया। बैठक में भाजपा के उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह के साथ राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 में से अधिक से अधिक सीट जीतने पर अपना सारा फोकस कर दिया है। लखनऊ में शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर इसको लेकर बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधामोहन सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तथा अन्य नेता मौजूद थे। भाजपा के इस बड़े मंथन के दौरान 2024 के लिए जमीनी रणनीति तैयार की गई। पार्टी प्रदेश मुख्यालय में सुबह दस बजे से दोपहर करीब एक बजे तक सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक के बार कोर टीम की बैठक हुई। बैठक में 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश, क्षेत्र, जिला, मंडल और बूथ स्तर के अभियान व कार्यक्रम तय किए गए हैं। इस बैठक में सभी बूथ के सशक्तिकरण के तीसरे चरण को लेकर चर्चा की गई। तय किया गया है कि जिन–जिन बूथों पर भाजपा को हार मिली है।

दिल्ली मेट्रो वायलेट लाइन पर सेवाओं में देरी

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने कहा कि दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन के बड़कल मोड़ स्टेशन पर एक यात्री के पटरियों पर उतरने से शुक्रवार को सेवाओं में देरी हुई। डीएमआरसी की वायलेट लाइन दिल्ली में कश्मीरी गेट और हरियाणा में राजा नाहर सिंह को जोड़ती है। डीएमआरसी ने ट्वीट किया, ''बड़कल मोड़ पर एक यात्री के पटरी पर उतरने के कारण बदरपुर बॉर्डर से राजा नाहर सिंह (बल्लभगढ़) तक सेवाओं में देरी। अन्य सभी लाइन पर सेवाएं सामान्य हैं।

अखिलेश यादव की ओर से 'तलाक' मिलने का इंतजार है:राजभर

बलिया (उत्तर प्रदेश)। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को

समाजवादी पार्टी (सपा) से बढ़ती तल्खी की खबरों के बीच कहा कि उन्हें अखिलेश यादव की तरफ से 'तलाक' मिलने का इंतजार है और वह सपा से गठबंधन तोड़ने को लेकर अपने स्तर से पहल नहीं करेंगे। सुभासपा और सपा के बीच तल्खी बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति पद के लिये विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की पत्रकार वार्ता में भी नजर आयी थी क्योंकि सपा ने इस पत्रकार वार्ता में गठबंधन के एक अन्य सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के प्रमुख जयंत सिंह को तो बुलाया था लेकिन सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर नजर नहीं आयें थे। मऊ जिले के मऊ में पार्टी की एक बैठक में सम्मिलित होने जा रहे सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर ने शुक्रवार को पीटीआई–से बातचीत में स्पष्ट किया कि वह सपा से गठबंधन तोड़ने को लेकर अपने स्तर से पहल नहीं करेंगे। उन्होंने सपा से तल्खी को लेकर मीडिया में आई खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ''उन्हें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से 'तलाक' मिलने का इंतजार है।'' उन्होंने कहा, ''वह अब भी सपा के साथ हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यदि उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहेंगे तो वह सपा के साथ जबरदस्ती नहीं रहेंगे।'' उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के समर्थन में आयोजित बैठक में सम्मिलित नहीं होने को लेकर पूछे जाने पर कहा कि अखिलेश यादव भूल गए होंगे, इसलिए उन्हें बैठक में नहीं बुलाया। राजभर ने एक सवाल के जबाव में कहा कि वह राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर समर्थन के मसले पर अपने फैसले की घोषणा 12 जुलाई को करेंगे।

चंडीगढ़ के स्कूल में गिरा 250 साल पुराना विशालकाय पेड़, 1 बच्चे की मौत, कई घायल

चंडीगढ़। सेक्टर–9 में स्थित कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में एक पेड़ गिरने की वजह से 1 बच्चे की मृत्यु और 13 बच्चे घायल हुए। बच्चे लंच टाइम में पेड़ के पास खेल रहे थे कि उसी समय यह पेड़ बच्चों पर गिरा। घायल बच्चों को जीएमएसएच अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसा स्कूल में लंच के समय हुआ। इस बड़े पेड़ के पास कई बच्चे खेल रहे थे तभी अचानक पेड़ बच्चों पर गिर गया। हादसे की सूचना मिलते ही अभिभावक भी स्कूल पहुंच गए हैं। गेट पर अभिभवाक हंगामा कर रहे हैं। यूटी के अधिकारी स्थिति का जायजा लेने स्कूल पहुंचे।

किसी के साथ छोड़ने से खत्म नहीं होती पार्टी:उद्धव

● शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि विधिमंडल पक्ष अलग होता है और पार्टी अलग चीज है। कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, इन्हें कोई ऐसे ही नहीं ले जा सकता है। धनुष–बाण को लेकर किसी भी प्रकार का मन में भ्रम न रखें। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने अपने खेमे में मौजूद 15–16 विधायकों की जमकर तारीफ की।

मुंबई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का लगातार नेता साथ छोड़ रहे हैं। इसी बीच उन्होंने कहा कि शिवसेना कोई चीज नहीं है कि कोई उसे चुकाकर ले जा सकता है। शिवसेना से कोई धनुष–बाण नहीं छीन सकता है। उन्होंने कहा कि पहला हमारा एक ही विधायक था लेकिन जब वो पार्टी छोड़कर गए तो क्या पार्टी समाप्त हो गई ? कितने भी हो 50 हो 100 हो, विधायक जा सकते हैं, पार्टी नहीं।

उद्धव ठाकरे ने कहा कि विधिमंडल पक्ष अलग होता है और पार्टी अलग चीज है। कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, इन्हें कोई ऐसे ही नहीं ले जा सकता है। धनुष–बाण को लेकर किसी भी प्रकार का मन में भ्रम न रखें। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने अपने खेमे में मौजूद 15–16 विधायकों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन विधायकों को विरोधियों ने अपने पाले में करने का प्रयास किया था लेकिन यह विधायक नहीं गए। इनकी जितनी तारीफ करो, उतनी कम है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिस पार्टी में रहते हैं, वहां जीत निश्चित है। असत्य मेव जयते जैसा कुछ नहीं है, जहां सत्य होती है वहां जीत निश्चित है। मुझे न्याय मंदिर पर विश्वास है।

ऑल्ट न्यूज के सह–संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

यूपी पुलिस को जारी हुआ नोटिस

नई दिल्ली। ऑल्ट न्यूज के सह–संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। आपको बता दें कि सीतापुर जेल मामले में मोहम्मद जुबैर को जमानत मिली है। हालांकि वो जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि मोहम्मद जुबैर दिल्ली पुलिस की न्यायिक हिरासत में रहेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह–संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उनके खिलाफ सीतापुर, उत्तर प्रदेश में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर यूपी पुलिस को नोटिस भी जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिनों के लिए अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी कि वे मामले से संबंधित मुद्दे पर कोई नया ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोन्साल्विस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उनके मुवक्किल मोहम्मद जुबैर को जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

विरोधियों को महुआ मोइत्रा का जवाब!

भाजपा बंगालियों को न सिखाए कि मां काली की पूजा कैसे करनी चाहिए

कोलकाता। देश में फिल्म काली के पोस्टर को लेकर विवाद मचा हुआ हैं। फिल्म के पोस्टर में मां काली को सड़क पर सिगरेट पीते दिखाया गया हैं। हिंदू धर्म की पूजनीय देवी काली को इस तरह चित्रित किए जाने को लेकर हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। फिल्म काली के पोस्टर पर छिड़ी बहस में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा भी शामिल हो गयी हैं। उन्होंने देवी काली को लेकर बयान दिया कि काली के कई रूप हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा था कि काली उनके लिए मांस खाने वाली, शराब स्वीकार करने वाली देवी थीं। मोइत्रा ने 5 जुलाई को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट 2022 में देवी काली को सिगरेट पीते हुए फिल्म काली के पोस्टर पर विवाद के जवाब में बोलते हुए यह बात कही। महुआ मोइत्रा के इस बयान के बाद देश में उनका विरोध होने लगा। महुआ मोइत्रा के विचारों पर लोग तीखी टिप्पणी करने लगी। महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवायी गयी। इस विवादित बयान पर तो महुआ का साथ खुद उनकी पार्टी ने ही छोड़ दिया। टीएमसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि महुआ मोइत्रा ने जो कुछ कहा है वह उनकी निजी विचारधारा है। पार्टी ऐसे किसी विचार का समर्थन नहीं करती हैं। बीजेपी महुआ मोइत्रा पर लगातार हमलावर हैं। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हिंदू देवी–देवताओं की संरक्षक नहीं है और उन्हें बंगालियों को देवी काली की पूजा करना नहीं सिखाना चाहिए। एक बंगाली समाचार चौनल से बात करते हुए, मोइत्रा ने कहा कि उन्होंने काली टिप्पणी विवाद पर बोलकर एक परिपक्व राजनेता के रूप में काम किया था, जबकि भाजपा अन्य जातीय समूहों पर हिंदुत्व के अपने एजेंडे को थोपने और अपने अखंड विचारों को थोपने का प्रयास करती है।

बंगालियों को भाजपा न सिखाए देवी काली की पूजा करना:महुआ

मां काली पर हाल में की गई विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निशाने पर आईं तृणमूल कांग्रेस की नेता एवं सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि भाजपा हिंदू देवी–देवताओं की संरक्षक नहीं है और उसे बंगालियों को नहीं सिखाना चाहिए कि मां काली की पूजा कैसे की जाती है। मोइत्रा ने कहा कि भाजपा उत्तर भारत में देवी–देवताओं की पूजा की विधियों पर आधारित अपने विचारों को देश के अन्य हिस्सों के उन लोगों पर नहीं थोप सकती है।

वैशवारा, हिन्दी साप्ताहिक
जौनपुर, सोमवार, 11 जुलाई, 2022

सम्पादकीय.....

भारत में विविधता और लोकतंत्र

दुनियाभर के मुसलमानों द्वारा इस्लाम को शांति के धर्म के रूप में दावा किया जाता है. धार्मिक ग्रंथ भी स्पष्ट रूप से शांति, शिक्षा और मानवता की सेवा करने का आदेश देते हैं. लेकिन इस्लाम के अनुयायियों के आचरण के बारे में आम धारणा दावे के विपरीत है. सार्वजनिक स्थानों पर हमारा व्यवहार, सामाजिक और राजनीतिक कार्य, समाज की अनदेखी और सामान्य शिष्टाचार में कमी हमारे दावों पर सवालिया निशान लगाते हैं. किसी भी समुदाय, समाज या राष्ट्र के बारे में धारणा उसके सामूहिक चरित्र, आचरण और योगदान के आधार पर बनती है. हर समुदाय या राष्ट्र में अच्छे लोग होते हैं, लेकिन राय बहुमत के व्यवहार और कार्यों के आधार पर बनती है. विचारों को थोड़े समय के लिए विकृत किया जा सकता है, लेकिन अगर लोगों का एक बड़ा वर्ग लंबे समय तक एक राय रखता है, तो यह समय ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करने और खुद को सुधारने का है, न कि उन्हें इस्लामोफोबिया बताकर स्वीकार करने से इनकार करने का. भारतीय मुसलमानों की बात करें, तो हमें ट्रिपल टैक्स यानी तिहरा कर चुकाना पड़ रहा है– पहला, 700 साल के मुस्लिम शासन की विरासत, जिस पर हम अपना दावा करते हैं, दूसरा, मुस्लिम दुनिया में होनेवाली घटनाएं, सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक और तीसरा, घरेलू सामाजिक–धार्मिक मुद्दे और एक गलत पड़ोसी देश का अस्तित्व. कुल मिलाकर, भारत में बहुसंख्यकों की मुसलमानों के बारे में राय नकारात्मक बनती जा रही है और एक वर्ग तो मुस्लिम विरोधी भावनाओं से पीड़ित हो रहा है. सभ्यता की उन्नति में मुस्लिम दुनिया के निम्न योगदान के कारण भी हमारी छवि खराब है, चाहे वह आधुनिक विज्ञान हो या प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, उद्योग या यहां तक कि सामाजिक सेवाएं. उपभोक्तावादी जीवनशैली, धर्म और राजनीति की अधिकता भरी खुराक एवं परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की कमी के परिणामस्वरूप हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में गिरावट जारी है. आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास पर ध्यान न देने, संस्थानों की शक्तियों का लाभ उठाने में विफल रहने और तेजी से विकसित हो रही विश्व आर्थिक व्यवस्था के साथ तालमेल न रखने से समुदाय प्रगति के अधिकतर मापदंडों में पिछड़ रहा है. हालांकि, आत्मनिरीक्षण और कार्यशैली को सही करने के लिए यह सही समय है. भारतीय मुसलमान भाग्यशाली हैं कि वे विशाल सामाजिक विविधता और परिपक्व लोकतंत्र के लाभांश का निरंतर आनंद ले रहे हैं. आज मुस्लिम महिलाओं और युवाओं में नया आत्मविश्वास आया है तथा शिक्षा, सामाजिक कार्यक्रमों एवं सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में समुदाय की भागीदारी में सुधार हुआ है. वर्तमान समय में जो चिंताजनक माहौल हमारे चारों ओर है, उससे छुटकारा पाने के लिए देश को धार्मिक कट्टरता और सभी प्रकार के अतिवाद के खिलाफ उठ खड़े होने और आवाज उठाने का समय आ गया है. धर्मांध तत्वों और ऐसी मानसिकता बनाने में सहयोग करनेवाले लोगों को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अगर इन्हें कोई भी रियायत दी गयी, तो ये लोग समाज को चैन से जीने नहीं देंगे. यह भारत और दुनियाभर के मुसलमानों के लिए भी मूल कारण को समझने और इस्लाम के कट्टर रूपों व सोचों के खिलाफ उठने का समय है. इनमें कुछ धाराएं ऐसी हैं, जिन्हें वैश्विक शक्तियों के इशारे पर बनाया गया है और उन्हें विभिन्न देशों में निर्यात किया गया है. चरमपंथी विचारधारा का पालन करने वाले एक छोटे से वर्ग के लिए मुस्लिम समुदाय ने पर्याप्त कीमत चुकायी है. उसकी धार्मिकता पर भी इससे नकारात्मक असर पड़ा है. इसके साथ ही समूचा समुदाय आज अन्य समुदायों के सामने सवालों से घिर गया है. ऐसी शिक्षण सामग्री और ऐसे संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करने का भी समय है, जो अतिवाद का प्रचार कर रहे हैं तथा कट्टर मानसिकता पैदा कर रहे हैं. अब इसमें किसी तरह की देरी करने या ढीला बर्ताव करने की कोई गुंजाइश नहीं रह गयी है. भारतीय मुसलमान बहुत ही विविधता भरे बहुसांस्कृतिक समाज में पैदा होने के लिए भाग्यशाली हैं, जो दूसरों के विश्वास और करुणा एवं आवास का सम्मान करने के मूल्यों को सिखाता है. असहिष्णुता या उग्रवाद की इसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. दुर्भाग्य से, देश में सांप्रदायिक माहौल में खतरनाक वृद्धि हो रही है, जो न तो लोकतंत्र के लिए और न ही अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है तथा निश्चित रूप से तेजी से बढ़ती वैश्विक शक्ति के रूप में भारत में इसका कोई स्थान नहीं है. सत्ताधारी वर्ग को इस गंभीर चुनौती का तत्काल संज्ञान लेना चाहिए. समानता, समावेश और विविधता के उभरते वैश्विक दर्शन तथा बहुसंस्कृतिवाद के मूल्यों और समझ के साथ भारतीय मुस्लिम समुदाय विश्व के मुसलमानों को रास्ता दिखा सकता है एवं अपने लिए समृद्ध लाभांश प्राप्त कर सकता है. समुदाय को आधुनिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि तेजी से उभरते आर्थिक अवसरों का लाभ उठा सके. तथा राष्ट्रीय लोकाचार एवं सामान्य सांस्कृतिक मूल्यों की बेहतर समझ विकसित हो सके, जिससे धारणाओं में सकारात्मक बदलाव होने के साथ–साथ शांति और सामान्य प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों एवं विभागों में डेढ़ साल के भीतर 10 लाख नियुक्ति का निर्देश दिया है. दिसंबर, 2021 में संसद में बताया गया कि केंद्र सरकार के विभागों में एक मार्च, 2020 तक 8.72 लाख पद खाली हैं. अधिकांश पद रक्षा, गृह, डाक, रेलवे व राजस्व विभाग से संबंधित हैं. बड़ी संख्या में युवाओं की पहली पसंद सरकारी नौकरी होती है. ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा नौकरियों की घोषणा युवाओं के लिए बड़ा राहतकारी फैसला है. विभिन्न विभागों में खाली पदों के भरे जाने से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा और सरकार की प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, लेकिन केवल सरकारी नौकरियों द्वारा ही रोजगार की चुनौतियों का सामना नहीं हो सकेगा. पिछले पांच–छह वर्षों से बेरोजगारी ऊंचे स्तर पर है. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2017–18 में बेरोजगारी चार दशक के ऊंचे स्तर पर रही. कोरोना काल में सरकार ने उद्योग–कारोबार से घटते रोजगार को बचाने के लिए अनेक पहल की. साथ ही, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष वित्तीय योजनाएं शुरू हुईं. वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ–साथ आमदनी, मांग, उत्पादन और उपभोग में वृद्धि से रोजगार की चुनौती कम करने की कोशिश की. फिर भी, सख्त लॉकडाउन से उपजी बेरोजगारी का असर अभी बना हुआ है. अब रूस–यूक्रेन युद्ध से उद्योग–व्यापार में मंदी की चिंता बढ़ रही है. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल, 2022 में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.83 फीसदी हो गयी और मई, 2022 में यह घटकर 7.12 फीसदी पर रही. जनवरी से मार्च 2022 की अवधि पर आधारित सावधिक श्रम शक्ति सर्वे (पीएलएफएस) की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि रोजगार सृजन की स्थिति सुधारना जरूरी है. साथ ही, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में श्रमिकों की तादाद भी बढ़ानी होगी. वर्ष 1991 से उदारीकरण शुरू होने के करीब तीन दशक बाद अब निजी क्षेत्र रोजगार के मामले में सरकारी क्षेत्र से बहुत आगे हैं. निजी क्षेत्र में स्वरोजगार, उद्यमिता और स्टार्टअप में रोजगार के अवसर बन रहे हैं. वित्त मंत्रालय की मई, 2022 की बुलेटिन के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021–22 में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के सब्सक्राइबर्स में रिकॉर्ड 1.2 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है. देश में अस्थायी और ठेके पर काम करनेवाले कामगारों (गिग वर्कफोर्स) की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है. नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में करीब 77 लाख गिग वर्कफोर्स है. इसकी संख्या 2029–30 तक 2.35 करोड़ होगी. लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या बिना प्लेटफॉर्म खानपान पहुंचाने वाले, कैब सेवाएं देने वाले, अन्य सर्विस व मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिग वर्कर्स के सामने सामाजिक सुरक्षा की बड़ी चिंताएं हैं. इन क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ–साथ नयी पीढ़ी को तैयार करने की रणनीति पर ध्यान देना होगा. अब देश और दुनिया में परंपरागत रोजगारों के समक्ष चुनौतियां बढ़ गयी हैं और डिजिटल रोजगार छलांग लगाकर बढ़ते हुए दिखायी दे रहे हैं. कोविड–19 ने नये डिजिटल अवसर पैदा किये हैं, क्योंकि ज्यादातर कारोबारी गतिविधियां अब ऑनलाइन हो गयी हैं. वर्क फ्रॉम होम करने की प्रवृत्ति को व्यापक तौर पर स्वीकार्यता से आउटसोर्सिंग को बढ़ावा मिला है. स्पष्ट है कि ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते जहां कई क्षेत्रों में रोजगार कम हो रहे हैं, वहीं डिजिटल अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़ रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन और डेटा साइंस जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों में प्रतिभा की मांग, प्रतिभा आपूर्ति की तुलना में 15 से 20 गुना अधिक हो सकती हैं. रोजगार के लिए लगातार नये–नये स्किल्स सीखना जरूरी होता जा रहा है. इस समय कोविड–19 और यूक्रेन युद्ध की वजह से पैदा हुए रोजगार संकट को दूर करने के लिए सरकार को नये सिरे से सोचने की जरूरत है. साल 1930 की महाआर्थिक मंदी के समय अर्थशास्त्री कींस ने मंदी का अर्थशास्त्र प्रस्तुत करते हुए लोक निर्माण कार्यों को रोजगार एवं आय को बढ़ाने का महत्वपूर्ण आधार बताया था. इसी तरह, 1933 से 1938 के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा चलाये गये इतिहास प्रसिद्ध न्यू डील कार्यक्रम का मकसद भी आर्थिक मंदी के संकट में लोक निर्माण परियोजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देना था. रोजगार चुनौतियों के मद्देनजर राष्ट्रीय एवं स्थानीय दोनों ही स्तरों पर लोक निर्माण कार्यक्रम से रोजगार बढ़ाना जरूरी हो गया है. जिस तरह गांवों में मनरेगा रोजगार का प्रमुख माध्यम बन गया है, उसी तरह शहरी बेरोजगारों के लिए भी योजना की जरूरत है. हम उम्मीद करें कि केंद्र सरकार अपनी घोषणा के अनुरूप आगामी डेढ़ वर्ष में 10 लाख नयी नौकरियों के मौके युवाओं की मुट्ठियों में सौंपने में कामयाब होगी. हम उम्मीद करें कि केंद्र सरकार की तरह राज्यों में भी राज्यस्तरीय नयी नौकरियों के लिए भर्ती का बड़ा अभियान चलाया जायेगा. सरकार को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए. डिजिटल प्रतिभाओं की कमी के परिदृश्य को ध्यान में रखकर नयी पीढ़ी को एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग एवं अन्य नये डिजिटल स्किल्स के साथ अच्छी अंग्रेजी, कंप्यूटर दक्षता तथा कम्युनिकेशन स्किल्स से सुसज्जित करने के लिए हरसंभव प्रयास करना होगा. इससे नयी पीढ़ी नये डिजिटल मौकों को भुना पायेगी. नीति आयोग ने सेवा क्षेत्र में अस्थायी तौर पर काम करने वाले जिन लाखों गिग वर्कर्स के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा की जरूरत बतायी है, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए नयी नीति निर्धारित होनी चाहिए. ऐसे प्रयासों से नयी पीढ़ी के लिए रोजगार की चुनौतियां कम होंगी. इससे जहां नयी पीढ़ी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकेगी, वहीं रोजगार अवसरों के बढ़ने से अर्थव्यवस्था में नयी मांग का निर्माण होगा. इससे अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी.

बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात न कहेंगे

सर्वमित्रा सुरजन

लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इन दोनों के बीच की कड़ी पर चलने के लिए अत्यधिक न्यायिक कौशल की आवश्यकता होती है। यह एक पहेली है जो प्रत्येक न्यायाधीश को निर्णय लिखने से पहले परेशान करती है। ये उद्गार हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जे.बी.पारदीवाला के। बीते रविवार को एक कार्यक्रम में लोकप्रिय जनभावनाओं के ऊपर कानून के शासन की प्रधानता पर जोर देते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि एक ओर बहुसंख्यक आबादी के इरादे को संतुलित करना और उसकी मांग को पूरा करना तथा दूसरी ओर कानून के शासन की पुष्टि करना कठिन काम है। माननीय न्यायाधीश की बातों से यही समझ आता है कि न्याय व्यवस्था में भी बहुसंख्यक वर्ग अपना दबदबा कायम रखना चाहता है और अपने मन की बात करना चाहता है, और ऐसे में न्याय की आसंदी पर बैठे लोगों के लिए निष्पक्ष फैसले देना बड़ी चुनौती है। जस्टिस पारदीवाला की इस टिप्पणी के बाद ही कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एचपी संदेश ने सोमवार को आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) की खिंचाई करने पर उन्हें तबादला करने की धमकी दी गई। मतलब न्यायपालिका में जिस चुनौती की बात रविवार को हो रही थी, सोमवार को उसका एक जीवंत उदाहरण पेश हो गया। इस बीच मंगलवार को लंदन में एक कार्यक्रम में भारत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन ने कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था स्वतंत्र है, कानून के शासन को सर्वोच्च रखा जाता है और इस वजह से निवेशकों के लिए भारत एक पसंदीदा विकल्प हो सकता है। सप्ताह के तीन दिनों में ही न्याय व्यवस्था के तीन अलग–अलग रंग देखने मिले, सात दिनों में विविध विचारों का पूरा इंद्रधनुष तैयार हो जाएगा। बहरहाल, लौटते हैं न्यायाधीश पारदीवाला की बातों पर, क्योंकि उससे प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर पर विचार का एक मौका मिला है। पाठक जानते हैं कि इस कहानी में दो गहरे दोस्त दो अलग–अलग परिस्थितियों में एक–दूसरे के खिलाफ बुलाई गई पंचायत में पंच की गद्दी पर बैठते हैं और वहां बैठते ही उन्हें अपनी गहन–गंभीर जिम्मेदारी का अहसास होता है। उसके बाद दोस्ती और दुश्मनी की भावनाओं से परे होकर वे तथ्यों और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाते हैं। न्याय व्यवस्था के इस उलझन काल में इस कहानी को फिर से पढ़ने की जरूरत है। और अगर पढ़ने में दिलचस्पी न हो तो इस के कुछ उद्धरण अदालती इलाके में चस्पा कर लेना चाहिए। जैसे खाला अलगू चौधरी से पंचायत में आने कहती हैं तो अलगू कहते हैं कि जुम्मन मेरा पुराना मित्र है। उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। तब खाला कहती हैं कि बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? जब पंचायत लगती है तो अलगू चौधरी को ही पंच बनाया जाता है। अलगू फिर अपनी दोस्ती का हवाला देते हैं तो खाला कहती हैं कि बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है, वह खुदा की तरफ से निकलती है। कहानी के दूसरे हिस्से में जब अलगू चौधरी और समझू साहू के बीच बैल को लेकर विवाद होता है और जुम्मन शेख पंच बनते हैं। यहां जुम्मन अलगू से कहते हैं कि पंच के पद पर बैठ कर न कोई किसी का दोस्त होता है, न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। अगर देश की तमाम अदालतों में न्याय के सिवा और कुछ न सूझने वाला माहौल पैदा हो जाए, अगर न्याय की आसंदी पर बैठे लोग यह मान लें कि बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात न करेंगे, तो नाइंसाफी की गुंजाइश ही कहां बचेगी। लेकिन दुख इस बात का है कि अब माहौल ऐसा नहीं रहा है। इसलिए कभी न्यायाधीशों को प्रेस कांफ्रेंस कर अपनी पीड़ा व्यक्त करनी पड़ती है, कभी प्रधान न्यायाधीश की ओर से टिप्पणी आती है कि सत्ताधारी दल मानता है कि हर सरकारी कार्रवाई न्यायिक समर्थन की हकदार है। प्रधान न्यायाधीश ये भी कहते हैं कि हम केवल संविधान के प्रति जवाबदेह हैं। जब इस तरह की सफाई देने की नौबत आने लगे तो ये समझ आने लगता है कि न्याय व्यवस्था दबावों और उलझनों से गुजर रही है। जैसे न्यायमूर्ति पारदीवाला ने ये भी कहा कि संविधान के तहत कानून के शासन को बनाए रखने के लिए देश में डिजिटल और सोशल मीडिया को अनिवार्य रूप से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह लक्ष्मणरेखा को पार करने और न्यायाधीशों पर व्यक्तिगत, एजेंडा संचालित हमले करने के लिए खतरनाक है। उनकी यह टिप्पणी शायद नूपुर शर्मा विवाद के बाद सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चली मुहिम से निकली है। पाठकों को जानकारी होगी कि नूपुर शर्मा ने अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों को दिल्ली लाने की याचिका अदालत में दाखिल की थी, जिसे नामंजूर करते हुए अदालत ने उन्हें देश में बिगड़ रहे हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया था और टीवी पर आकर माफी मांगने की नसीहत भी दी थी। नूपुर शर्मा पर कड़ी टिप्पणी न्यायमूर्ति पारदीवाला ने की थी। जिसके बाद सोशल मीडिया पर अदालत के इस रवैये की खूब आलोचना हुई। देश में रोजाना अन्याय होते देख कर भी चुप रहने वाले लोग अचानक न्यायाधीशों को उनका फर्ज और सीमाएं याद दिलाने लग गए। मुखालफत की ये मुहिम सोशल मीडिया तक ही नहीं रुकी, अब 15 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, 77 सेवानिवृत्त नौकरशाहों और 25 सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के अधिकारियों सहित कुल 117 विशिष्ट लोगों ने इस मामले में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पारदीवाला की टिप्पणियों के खिलाफ एक खुला बयान जारी किया है। जिसमें संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देते हुए कहा गया है कि श्रेष्ठम जिम्मेदार नागरिक के तौर पर यह मानते हैं कि किसी भी देश का लोकतंत्र तब तक ही बरकरार रहेगा, जब तक कि सभी संस्थाएं संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करती रहेंगी। उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों की हालिया टिप्पणियों ने लक्ष्मणरेखा पार कर दी है और हमें एक खुला बयान जारी करने के लिए मजबूर किया है। पता नहीं बयानवीरों को सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग यहां तक कि सरकार के कामकाज में कभी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन क्यों नजर नहीं आया। और बयान देने की ऐसी मजबूरी उन्हें पहले क्यों महसूस नहीं हुई। खैर लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, इन लोगों को अभी न्यायपालिका की निष्पक्ष भूमिका पर खतरा दिखा तो आपत्ति दर्ज करा दी। काश आपत्ति दर्ज कराने का ऐसा खुला माहौल सबके लिए बना रहे और हमेशा बना रहे तो फिर कोई भी पद का अहंकार नहीं दिखा पाएगा, हमेशा एक संतुलन कायम रहेगा। वैसे लक्ष्मणरेखा की बात तो जस्टिस पारदीवाला ने भी की है और वे मानते हैं कि डिजिटल और सोशल मीडिया को व्यवस्थित करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह के शाब्दिक हमले उन पर किए गए, वैसे कई हमले तो एक अरसे से इस देश के जागरुक और संविधाननिष्ठ नागरिक झेलते आए हैं। पानी में रहकर मगर से बैर करते हुए ये लोग धारा के विपरीत तैरने का साहस करते हैं ताकि ये देश और इसकी उदार लोकतांत्रिक परंपराएं बची रहें। यही साहस अगर सारे लोग मिलकर दिखाएं तो तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी। आखिरी बात, न्यायाधीशों की टिप्पणियों के खिलाफ सोशल मीडया पर जो मुहिम चली, उसे हैशटैग सुप्रीम कोठा के तहत चलाया गया। इसी तरह कुछ साल पहले एक केन्द्रीय मंत्री ने मीडिया के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए प्रेस्टीट्यूट शब्द का इस्तेमाल किया था। अपशब्दों का तो सारा वास्ता महिलाओं के अपमान से ही है, अब संस्थाओं की आलोचना के लिए भी महिला विरोधी शब्दों का इस्तेमाल होने लगा है। इस देश में महिलाओं की नियति क्या अपमानित होना ही है।

नए शिक्षा सत्र से उम्मीदें

शिवनारायण गौर

एक जुलाई से लगभग सभी जगह नया शिक्षा सत्र शुरु हो चुका है। पिछले दो साल के बाद व्यवस्थित रूप से स्कूल खुल रहे हैं। गौरतलब है कि तकरीबन दो साल से बच्चे औपचारिक रूप से नियमित स्कूली शिक्षा से वंचित रहे हैं। खास तौर पर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये समय काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। गत वर्ष तक अमूमन तो काफी समय स्कूल बंद ही थे पर जहां खुले वहां भी कोविड के डर के चलते पालकों ने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल नहीं भेजा। ऐसी परिस्थिति में ऑनलाइन शिक्षा ही एक माध्यम था जिससे बच्चे अपनी औपचारिक शिक्षा जारी रखे हुए थे। पर ऑनलाइन शिक्षा की अपनी सीमाएं हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करना खासतौर उन बच्चों के लिए बड़ी चुनौती थी जो कि दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। जहां बिजली से लेकर मोबाइल और नेटवर्क की चुनौती अपने आप में एक मुश्किल बात थी। कहा जा सकता है कि इन दो सालों में ऑनलाइन शिक्षा ने हाशिए पर पड़े समुदाय के बच्चों को मुख्यधारा से काफी हद तक अलग कर दिया है। जिनके पास संसाधनों की पहुंच है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं, ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच केवल उन तक ही है। ऑनलाइन शिक्षा के बारे में कई रपटें इस दौरान आई हैं जिनसे जानकारी मिलती है कि प्राथमिक शिक्षा के लिहाज से ऑनलाइन शिक्षा बहुत कारगर नहीं हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा पांच राज्यों में ऑनलाइन शिक्षा की स्थिति पर किए गए एक सर्वेक्षण में शामिल 80 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों ने कहा कि वे ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने में असमर्थ थे, जबकि 90 प्रतिशत शिक्षकों ने महसूस किया कि बच्चों के सीखने का कोई सार्थक आकलन संभव नहीं था। हम जानते हैं कि छोटे बच्चों का सीखना एक दूसरे के साथ काफी होता है। साथ में खेलना, अपने हमउम्र से बातचीत में बच्चों को एक–दूसरे से जानने और सीखने के मौके भी मिलते हैं और इन मौकों से बच्चे दूर हो गए थे। हिन्दी भाषी समाज में पढ़ने की आदत का अभाव भी इसका एक कारण है कि बच्चे शिक्षा की प्रक्रिया से जुड़ने में ज़्यादा समय लेते हैं। अब जब बच्चे ऑनलाइन से ऑफलाइन शिक्षा के लिए स्कूल में आ रहे हैं तो स्कूल की भूमिका काफी बढ़ जाती है। दो साल के इस लम्बे व्यवधान के बाद यदि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं तो स्कूल को उनके साथ ज़्यादा काम करने की जरुरत होगी। संभावना है कि उनके अकादमिक स्तर में कमी आई होगी। हाल ही में अक्सर 2021 की रपट भी इस बात का जिक्र करती है कि बच्चों के अकादमिक स्तर में कमी आई है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 10 वीं कक्षा के 66 फीसदी बच्चों को गणित, 65 फीसदी को साइंस और 58 फीसदी बच्चों को अंग्रेजी भाषा का बुनियादी स्तर का ज्ञान भी नहीं है। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले 52 प्रतिशत बच्चों को गणित का जोड़ घटाना भी नहीं आता है। यह सर्वे मध्य प्रदेश के 2320 स्कूलों के 38778 बच्चों के साथ किया गया था। ये अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि शिक्षा की गुणात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यही नहीं इस दौरान उन बच्चों पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जिनका स्कूल में दाखिला होना था।

बुजुर्गो की देखभाल

परिवार और समाज में बड़े–बुजुर्गों की सेवा हमारी संस्कृति की विशिष्टता रही है, पर कई कारणों से यह दायित्व ठीक से नहीं निभाया जा रहा है. इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से बड़ी पहल की जा रही है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक लाख सेवा दाताओं को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जो बुजुर्गों की देखभाल करने का जिम्मा संभालेंगे. सितंबर में ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध हो जायेगा, जिसके माध्यम से प्रशिक्षित लोगों की सेवाएं ली जा सकेंगी. वर्तमान समय में ऐसी सेवाएं महंगी भी हैं और अक्सर ऐसे लोग उपलब्ध होते हैं, जो ठीक से प्रशिक्षित नहीं होते क्योंकि आपूर्ति की तुलना में मांग बहुत अधिक है. इन सेवाओं को हासिल करने में भी मुश्किलें आती हैं. बुजुर्ग या उनके परिवार के पास सही जानकारियां नहीं होती हैं. केंद्र सरकार की इस पहल से इन समस्याओं का भी समाधान होगा तथा रोजगार के अवसर भी मिलेंगे. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव आर सुब्रमण्यम के अनुसार, सरकार प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानदंडों का निर्धारण करेगी तथा ऐसी सेवाओं को समुचित मूल्य पर मुहैया कराने का प्रयास किया जायेगा. आर्थिक कारणों से कई परिवारों में बुजुर्गों की देखभाल ठीक से नहीं होती है. हेल्पएज इंडिया के एक हालिया सर्वेक्षण में बताया गया था कि 29 फीसदी लोग अपने माता–पिता को घर में नहीं रखना चाहते हैं. हमारे देश में 47 फीसदी बुजुर्ग परिवार पर निर्भर हैं. अधिक उम्र के कारण 71 फीसदी बुजुर्ग काम नहीं करते, लेकिन 36 फीसदी लोग काम करना चाहते हैं और 40 फीसदी तो जब तक संभव हो सके, काम करने की इच्छा रखते हैं. इस सर्वेक्षण में यह तथ्य भी सामने आया कि 67 फीसदी बुजुर्गों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है।

वैशवारा, हिन्दी साप्ताहिक
जौनपुर, सोमवार, 11 जुलाई, 2022

ईदुल अजहा पर विशेष

कुर्बानी दिखावा नहीं बल्कि अल्लाह कि रजा के लिए होनी चाहिए

कुर्बानी का जानवर बे ऐब और तंदरुस्त होना जरूरी है

लखनऊ(यूएनएस)। इस्लाम में कुर्बानी की बड़ी अहमियत है। इस्लामी साल का महीना ही कुर्बानी से शुरु होता है। और खत्म भी कुर्बानी पर होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक कुर्बानी का अमल बहुत ही प्यारा अमल है। अब कुर्बानी चाहे पैसे की हो, जानवर की हो या फिर ख्वाहिशात की। कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक बहुत पसंद दीदा अमल है। लेकिन कुर्बानी अल्लाह पाक की रजा के लिए होना चाहिए ना कि आपनी अना या जात के लिए, कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्स्लां की सुन्नत है। हजरत इब्राहिम अल्लाह के पैगंबर हैं। आपने तमाम उम्र अल्लाह के बन्दों की खिदमत में गुजार दी, करीब 90 साल की उम्र तक उनके कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथों को बुलंद कर दुआ की। और पर्वर्दिगार ने अपने दोस्त यानी खलील की दुआ को कुबूल कर उन्हें चाँद–सा बेटा इस्माइल अलैहिस्स्लां की शक्ल में अता फरमाया। आपको बताते चलें कि इस्माईल थोडे से बड़े हुए थे कि हजरत इब्राहिम को ख्वाब में अल्लाह का हुकुम हुआ कि इब्राहीम कुर्बानी करो, रिवायत के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्स्लाम ने 100 बकरे कुर्बान कर दिये फिर ख्वाब आया की कुर्बानी करो आपने फिर 100 ऊंट कुर्बान किये आपने फिर ख्वाब देखा अपनी सबसे प्यारी चाहने वाली चीज की कुर्बानी दो, यानी अपने बेटे को कुर्बान करो, तब इब्राहीम अलैहिस्स्लां ने अपने बेटे इस्माइल को तय्यार किया। और कुर्बानी के लिये जंगल की तरफ सुनसान मकाम पर ले गए और आपनी तथा अपने बेटे की आंख पर पट्टी बान्ध कर छुरी चला दी। यह अदा उस रब्बुल इज्जत को इतनी पसन्द आई कि उसने कयामत तक के लिये इसको हर साहिबे इस्ततात यानी हर पैसे वाले पर वाजिब करार दे दिया,तब से आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान इस सुन्नत को हर साल अदा करते हैं। कुर्बानी के इस अमल से दुनिया में यह पैगाम भी जाता है। की कुर्बानी एक अच्छी चीज है। बशर्ते वो दिखावा ना होकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिये हो,और कुर्बानी सिर्फ जानवर की ही नहीं,नफ्स की भी हो कुर्बानी ख्वाहिशात की भी ही तभी अल्लाह पाक के नजदीक काबिले कुबूल होगी, कुछ मुस्लिम परिवारों में कुर्बानी के लिए बकरे को पालपोसकर बड़ा भी किया जाता है। और फिर ईदुल अजहा यानी बकरीद पर उसकी कुर्बानी दी जाती है। और जो लोग बकरे को नहीं पाल पाते हैं। और फिर भी उन्हें कुर्बानी देनी चाहते है। उन्हें कुछ दिन पहले बकरा खरीदकर लाना होता है। ताकि उस बकरे से उन्हें लगाव हो जाए, कुर्बानी का एक अहम बात को अक्सर लोग भूल जाते हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से कुर्बानी करना चाहिए कुर्बानी का सबसे पहला मसला, जिस जगह पर जानवर को कुर्बान किया जाए वह जगह पूरी तरीके साफ कर ली जाए फिर छोरी में धार तेज कर ली जाए कुर्बानी के जानवर का खून गड्ढे में जाए नाली में कतई नहीं जाना चाहिए या फिर बालू मिट्टी में हो कुर्बानी के जानवर का खून नाली में बहना कुर्बानी की बे अदबी है। कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए। कुर्बानी का जानवर खूबसूरत और तंदुरुस्त एवं बे ऐब होना चाहिए। जिस पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी का जानवर दो या चार दांत का होना चाहिए। लेकिन लोग अपना वक्त बचाने एवं मात्र औपचारिकता निभाने के लिए पत्ती यानी हिस्सा ले लेते हैं। और जानवर तक नहीं देखते, जबकि जिस जानवर में पत्ती ली गई है उस जानवर को देखना जरूरी है।

सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें विषय पर जागरूकता कार्यक्रम

लखनऊ(यू एन एस)। नवयुग कन्या महाविद्यालय राजेंद्र नगर लखनऊ की 19 उत्तर प्रदेश गर्ल्स बटालियन एनसीसी विंग के द्वारा प्राचार्या प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय तथा मेजर डॉ. मनमीत कौर सोढ़ी के नेतृत्व में आज पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 'सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें–इस विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैडेट्स ने पोस्टर,स्लोगन व संवाद के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक के द्वारा पर्यावरण एवं प्राणी मात्र के जीवन को होने वाले नुकसान के विषय में बताया। इसके अतिरिक्त कैडेट्स मेजर (डॉ) मनमीत कौर सोढ़ी के दिशा निर्देशन में एक वीडियो भी तैयार कर रही हैं जिसमें कैडेट अनन्या पाठक, प्रिया यादव, वर्षा यादव, जया दुबे, प्रियंका गुप्ता, सौम्या हरशीन कौर,रोशनी सिंह थापा, नंदिनी सिंह,तनुजा, स्वाति त्रिपाठी, अनामिका यादव, रिया कश्यप,पंखुरी, सोनी सिंह,तनु सारस्वत, कीर्ति रस्तोगी, अंजली राय, कीर्ति मिश्रा, प्रियांशी और अर्पिता ने इस बात को विस्तृत तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि प्लास्टिक क्या है, इसका प्रयोग कितने रूपों में होता है।

प्लास्टिक के कितने प्रकार हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, इससे पर्यावरण को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसका विकल्प क्या हो सकता है ,और एक एनसीसी कैडेट के रूप में हम सबकी इस संबंध में क्या जिम्मेदारी बनती है? प्लास्टिक का प्रयोग न केवल मनुष्य अपितु सभी जीवों के लिए हानिकारक है। ग्रीन हाउस गैसों को भी प्रभावित कर रहा है। सुविधाजनक मानकर हम इसे अपनी आदत बना लेते हैं परन्तु जब वही सुविधा जीवन के लिए संकट बन जाए तो उसे छोड़ देना ही हितकर है। केवल प्रतिबंध के द्वारा ही इसके प्रयोग को नहीं रोका जा सकता बल्कि सभी नागरिकों के सहयोग से ही इस पर नियंत्रण संभव है। हम सभी को अपने स्तर से अपने पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व का निवर्हन करना होगा तभी स्वच्छ व स्वस्थ्य समाज का निर्माण संभव हो सकेगा। प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय ने कैडेट्स के प्रयास की सराहना करते हुए उन्हें सदैव समाज उपयोगी कार्य में प्रवृत्त रहने के लिए प्रेरित किया। जागरूकता अभियान में कैडेट खुशी सिंह,श्रुति तिवारी, गरिमा बाजपेई, त्रिनेत्री शर्मा, खुशी कनौजिया, सगलगुण कौर, आकांक्षा पाल, श्रेया पांडे, आरुषि शुक्ला समेत बड़ी संख्या में कैडेट्स ने प्रतिभाग किया।

रोके गए और महंगाई भत्ते का भुगतान तत्काल किया जाए : महासंघ

लखनऊ(यूएनएस)। कोरोना काल में रोके गए भत्तों के साथ महंगाई भत्ते की मांग प्रदेष के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ द्वारा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष रामराज भी प्रदेश महामंत्री सुरेश सिंह यादव ने आज मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित करते हुए जनवरी 2022 से देय तीन महंगाई भत्ते का तत्काल भुगतान करने की मांग किया है। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर महंगाई भत्ते का भुगतान होता है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए जनवरी 2022 से 3 प्रतिषत महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दिया है। यह वृद्धि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पिछले 6 माह से मिल रही है,जबकि प्रदेश सरकार के राज्य कर्मचारी अभी भी महंगाई भत्ते के भुगतान से वंचित है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सूत्रों के अनुसार महंगाई भत्ते का भुगतान मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद ही होता है। वित्त विभाग ने पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजी थी लेकिन वह पत्रावली उचित समय पर भेजने की टिप्पणी के साथ वापस आ गई थी। 7 माह का समय बीत गया है अभी तक प्रदेश कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के भुगतान का आदेश नहीं हुआ है ।सुरेश सिंह यादव ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में अवगत कराया है कि प्रदेश के कर्मचारियों आशा थी कि 100 दिनों के कार्यकाल की घोषणा के साथ प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की घोषणा भी होगी परंतु कर्मचारी निराश हाथ लगी। जबकि प्रदेश में राजस्व की स्थिति बेहतर है, कर्मचारी पूरी ईमानदारी निष्ठा एवं मनोयोग से कार्य कर रहा है। प्रदेश के कर्मचारियों के सात भत्ते करोना कॉल वित्तीय स्थिति खराब होने का हवाला देकर रोके गए थे उनका भी भुगतान किया जाए। उत्तर प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद 4.30 लाख, उनको भरा जाए।

पुलिस किसी को कभी भी रोक सकती है

लखनऊ(यूएनएस)। लखनऊ पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को आरटीआई में दी गयी सूचना में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने 21 से 23 अगस्त तथा फिर 27 अगस्त 2021 को अमिताभ और उनकी पत्नी डॉ नूतन ठाकुर को गोरखपुर और अयोध्या जाने से रोकते हुए नजरबंद किया था। पुलिस ने यह दावा किया है कि कानून व्यवस्था के दृष्टिगत कोई भी पुलिस अधिकारी किसी को भी कहीं जाने से मना कर सकता है, जिसके लिए अलग से किसी भी आदेश की जरुरत नहीं होती है. पुलिस ने कहा कि अमिताभ को कानून व्यवस्था के दृष्टिगत गोरखपुर और अयोध्या जाने से रोका गया और एसीपी गोमतीनगर ने उन्हें पूछे जाने पर लिख कर भी यह बात बताई थी। पुलिस ने कहा कि उनके पास इसके अलावा अन्य कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। अमिताभ के अनुसार पुलिस का यह जवाब बिलकुल गलत है क्योंकि किसी भी प्राधिकारी को किसी नागरिक को बिना पर्याप्त आधार और बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये मनमाने ढंग से रोके जाने का कोई अधिकार नहीं है।

नूतन ठाकुर अधिकार सेना में शामिल

लखनऊ(यूएनएस)। डॉ नूतन ठाकुर ने आज नवगठित अधिकार सेना की सदस्यता ग्रहण कर ली. उन्होंने कहा कि वे अधिकार सेना के उद्देश्यों से सहमत होने के कारण इसमें शामिल हो रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि पार्टी उनकी योग्यता के अनुरूप उन्हें कार्य और दायित्व देगी। नूतन ने कल आम आदमी पार्टी (आप)से यह कहते हुए त्यागपत्र दिया था कि वे लगातार अपनी शक्ति तथा क्षमता भर पार्टी का कार्य कर रही थी, किन्तु उनके बार–बार अनुरोध के बाद भी पार्टी के द्वारा उनकी योग्यता के अनुरूप कोई दायित्व नहीं दिया गया तथा उनकी उर्जा का समुचित उपयोग नहीं हो सका।

ऋषि के विचारों को समाज में पहुँचाने का समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है : उमानंद शर्मा

लखनऊ(यूएनएस)। गायत्री ज्ञान मंदिर इंदिरा नगर, लखनऊ के विचार क्रान्ति ज्ञान यज्ञ अभियान के अन्तर्गत लखनऊ से प्रकाशित एक समाचार पत्र के संदर्भ पुस्तकालय में गायत्री परिवार के संस्थापक युगऋषि पं0 श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा रचित सम्पूर्ण 79 खण्डों का 366वाँ ऋषि वांड़मय की स्थापना कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। उपरोक्त साहित्य गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट गायत्री मंदिर इन्दिरा नगर लखनऊ सक्रिय कार्यकर्ती ऊषा किरन सिंह निवासी रम्पुरा, फकीरे, पूरनपुर, पीलीभीत ने अपने प्रिय जीवनसाथी स्व0 कुँवर बैजनाथ सिंह की स्मृति में ज्ञान दान के रूप में भेंट किया एवं साथ–साथ पत्रकार बन्धुओं को युग निर्माण योजना का गायत्री विशेषांक भेंट किया। इस अवसर पर वाड्मय स्थापना अभियान के मुख्य संयोजक उमानंद शर्मा ने कहा कि ''ऋषि के विचारों को समाज में पहुँचाने का समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है। हम आशा करते हैं कि संपादक समाचार पत्र के माध्यम से ऋषि के विचारों को पहुँचाने का प्रयास करेंगे।

यूपी के आरटीआई प्रयोगकर्ताओं की समस्याओं के निराकरण की मांग

लखनऊ(यूएनएस)। विगत कई वर्षों से देश भर के आरटीआई प्रयोगकर्ताओं के हितों की बात कर रही सामाजिक संस्था सूचना का अधिकार बचाओ अभियान के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सूचना आयुक्त भवेश कुमार सिंह से भेंटवार्ता कर यूपी के आरटीआई प्रयोगकर्ताओं की समस्याओं के निराकरण की मांग उठा दी है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरटीआई एक्टिविस्ट एवं पत्रकार तनवीर अहमद सिद्दीकी, जैद अहमद फारूकी वरिष्ठ पत्रकार एवं आरटीआई एक्टिविस्ट, राम स्वरूप यादव सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट, अशोक कुमार शुक्ला अधिवक्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट, देवेश मणि त्रिपाठी अधिवक्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट, मो० सफीर सिद्दीकी मान्यता प्राप्त पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता ने मुख्य सूचना आयुक्त भवेश कुमार सिंह के बुलावे पर भवेश से भेंटवार्ता करके यूपी के आरटीआई प्रयोगकर्ताओं अनेकों समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए अनुरोध किया है कि वे प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करके इन समस्याओं का निराकरण करायेंगे। संस्था के प्रतिनिधिमंडल ने 20 बिन्दुओ की मांग उठाई हैं कि आयोग की सुनवाइयों में जन सूचना अधिकारियों, विभागों की तरफ से सरकारी खजाने से फीस लेकर आने वाले अधिवक्ताओं का सुनवाई कक्षों में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए,आयोग परिसर में मुख्य–मुख्य स्थानों पर विशाखा समिति से सम्बंधित सूचना पट तत्काल प्रदर्शित कराये जाएँ,आयोग के 'रूल्सऑफबिजनेस' बनाकर लागू करने के साथ साथ आयोग में दाखिल होने वाली अपीलों और शिकायतों का निपटारा अधिकतम 45 दिनों में किया जाए,उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किये गए आदेशों के अनुसार आयोग के सभी 11 सुनवाई कक्षों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित कराकर सभी सुनवाईयां सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में कराने की व्यवस्था लागू की जाए,आयोग के सभी 11 सुनवाई कक्षों में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की धारा 153ठ के अनुसार खुली सुनवाई की व्यवस्था लागू की जाए,जन सूचना अधिकारियों के खिलाफ एक्ट की धारा 20 (1) के तहत लगे अर्थदण्ड को विभाग के बजट से राजकोष में जमा करने की अनियमितता की जांच पिछले 10 साल के रिकॉर्ड के आधार पर कराई जाए,आयोग की वेबसाइट को तत्काल अपडेट कराकर एक्ट की धारा 4 (1) (इ) की लेटेस्ट सूचना आयोग की वेबसाइट पर तत्काल प्रदर्शित की जाए,आयोग आने वाले आरटीआई प्रयोगकर्ताओं की समस्याओं को जानने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित संख्या के आरटीआई प्रयोगकर्ताओं का रैंडम आधार पर चयन करके आयोग द्वारा निर्धारित समय अंतराल पर आरटीआई प्रयोगकर्ताओं, सूचना आयुक्तों व आयोग के पदाधिकारियों के मध्य बैठकों का आयोजन आरम्भ किया जाए, आयोग द्वारा पारित अंतिम व अंतरिम सभी आदेशों की नकल देने के लिए 10–का कोर्ट फी स्टाम्प लेने की व्यवस्था को समाप्त करके नकलें निःशुल्क दी जाएँ,आयोग की सुनवाइयों के अचानक स्थगन की सूचना आयोग की वेबसाइट पर तुरंत अपलोड करने के साथ साथ दोनों पक्षों के मोबाइल्स पर एस.एम.एस. द्वारा दिया जाना शुरू किया जाए,डिजिटल इंडिया के भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के एजेंडे के तहत सूचना आयुक्तों की सुनवाईयां यू–ट्यूब और फेसबुक आदि पर लाइव चलाया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई है कि भवेश कुमार सिंह यूपी के सूचना आयोग में व्याप्त समस्याओं का निराकरण करते हुए प्रदेश की योगी सरकार सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और पारदर्शिता–उन्मुख मंशा के अनुसार आयोग की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी और जबाबदेह बनाने के अपने पदीय दायित्व का निर्वहन अवश्य करेंगे स मुख्य सूचना आयुक्त से पूरी आशा और विश्वास होने की बात कहते हुए प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त भवेश कुमार सिंह इन सभी मांगों का स्वयं संज्ञान लेकर विचार करके आरटीआई आवेदनकर्ताओं की उपरोक्त समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करके हमें तत्परतापूर्वक अवगत अवश्य करायेंगे।

अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव ऊर्जा बने

गृह विभाग की पहले से ही थी जिम्मेदारी, पहले रह चुके हैं पावर कॉर्पोरेशन के एमडी

लखनऊ(यूएनएस)। शासन ने अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को ऊर्जा का अतिरिक्त कार्यभार भी दे दिया है। अभी तक पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज प्रमुख सचिव ऊर्जा का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे थे। इस बारे में नियुक्ति विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। रिटायरमेंट से करीब दो महीने पहले अवनीश अवस्थी को यह जिम्मेदारी दी गई है। उनके पास मौजूदा समय गृह विभाग की पूरी जिम्मेदारी थी। अवनीश अवस्थी इससे पहले पावर कॉरपोरेशन के एमडी रह चुके हैं। अखिलेश और मायावती दोनों ही सरकार में उनके पास यह जिम्मेदारी थी। अखिलेश यादव ने अवनीश अवस्थी को हटाकर एपी मिश्रा को एमडी बनाया था। यह उस समय की सबसे बड़ी घटना थी, जिसमें किसी आईएएस को हटाकर इंजीनियर को एमडी की जिम्मेदारी दी गई हो। अवनीश अवस्थी 1987 बैच के आईएएस अधिकारी है। विधान सभा चुनाव 2022 के समय इनका नाम विपक्ष की वजह से काफी चर्चा में आया था। तब कांग्रेस और सपा दोनों ही पार्टी ने इनको गृह विभाग से हटाने की मांग की थी। उस समय दलील दी गई थी कि अपने पद पर रहते हुए अवनीश अवस्थी चुनाव को प्रभावित कर सकते है। हालांकि, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की इस मांग को खारिज कर दिया था। पावर कॉर्पोरेशन सूत्रों का कहना है कि ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा से मौजूदा चेयरमैन एम देवराज का कुछ दिन पहले विवाद हो गया था। आलोक कुमार के जाने के बाद अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी भी प्रमुख सचिव ऊर्जा ही देख रहे थे। अब उनके पावर को कम करने के लिए अवनीश अवस्थी को लाया गया है। दरअसल, पिछले दो महीने से अभियंता संघ भी मंत्री से लगातार एम देवराज की शिकायत कर रहा था। ऐसे में इसको इंजीनियरों के दबाव के तौर पर भी देखा जा सकता है।

यूपी में अल्पसंख्यक समाज पर बीजेपी का जोर

योगी बोले, सकारात्मक सोच से आजमगढ़–रामपुर जीते, मिशन–2024 के लिए बूथों को 4 श्रेणी में बांटा

लखनऊ(यूएनएस)। यूपी में भाजपा ने मिशन–2024 को लेकर शुक्रवार को पार्टी कार्यालय लखनऊ में बड़ी बैठक की। 93 जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को टारगेट–80 के बारे में बताया गया। बूथों को 4 श्रेणी में बांटकर हर वर्ग से जुड़ने का प्लान तय हुआ। ए, बी, सी, डी श्रेणी में बूथों का बांटा गया है। सी श्रेणी में 25 हजार ऐसे बूथों को रखा गया है, जहां भाजपा लंबे समय से नहीं जीती।

सीएम योगी ने कहा कि लोग कहते थे कि अल्पसंख्यक समाज का वोट नहीं मिलता, लेकिन कार्यकर्ताओं के परिश्रम और सकारात्मक सोच से वहां जीत मिली। सीएम ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी बात की। सीएम ने कहा कि अटलजी की सरकार में एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया। मोदी सरकार में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने। अब एक बार फिर एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। सीएम योगी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह सहित सभी 75 जिलों से पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी बैठक में मौजूद रहे।

आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पहले रोडमैप पर मंथन हुआ। आजमगढ़ और रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में जीत से बेहद उत्साहित भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मिशन–80 का टारगेट सेट किया है।

इसके बाद से ही पार्टी यूपी पर फोकस करके अगले बड़े समर की तैयारियों में जुट गई है। सीएम योगी पहले ही इस मिशन की घोषणा कर चुके हैं। अब पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में है।

लोकसभा चुनाव में वोट परसेंट 50 से अधिक करने की योजना के तहत विभिन्न वर्गों को पार्टी से जोड़ने, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से लगातार संपर्क बनाने की रणनीति है। इसके साथ ही अलग–अलग धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच पहुंचकर सरकार और संगठन की बात को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसमें पार्टी ने युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, एससी–एसटी मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और ओबीसी मोर्चा की ओर से होने वाले कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे।

भारतीय संस्कृति में गुरु की बड़ी महत्व पूर्ण भूमिका : संत प्रमोद दास

लखनऊ(यू एन एस)। भागवत आश्रम, शिवाजी पुरम, इंदिरा नगर में शुक्रवार को प्रवचन करते हुए पूज्य संत प्रमोद दास जी महाराज ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु की बड़ी महत्व पूर्ण भूमिका है। गुरु पथ प्रदर्शक तो हैं ही साथ ही गुरु की सही लक्ष्य के निर्धारण में भी अहम भूमिका देखी जाती है अर्थात जीवन में सही लक्ष्यों के निर्धारण से लेकर लक्ष्य प्राप्ति तक गुरु की महिमा सर्व विदित है। उन्होंने कहा कि जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति, प्रभु की खोज, ब्रह्म बोध जैसे लक्ष्यों की पूर्ति में गुरु की महिमा सर्व शास्त्रों में प्रकाशित है। साथ ही यह भी आज्ञा है कि मनुष्य को शास्त्रज्ञ होने पर भी स्वतंत्रता पूर्वक ब्रह्म ज्ञान का अन्वेषण नही करना चाहिए अर्थात किसी न किसी गुरु के आश्रय में ही करना चाहिए। भारतीय संस्कृति ऋषि, गुरु प्रधान है। जिसमें गुरु के समीप रह कर उनके श्रीचरणों की सेवा करते हुए शास्त्र श्रवण की परंपरा रही है।

ब्रिगेडियर ने एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण किया

लखनऊ(यूएनएस)। 64 यूपी बटालियन एनसीसी लखनऊ द्वारा एएमसी सेन्टर एवं कालेज, लखनऊ कैण्ट में संचालित दस दिवसीय एनसीसी कैम्प का ग्रुप मुख्यालय लखनऊ के ग्रुप कमाण्डर ब्रिगेडियर रवि कपूर ने दौरा किया। इस दौरान कैम्प कमाडेंट एवं 64 यूपी बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल गौरव कार्कीने ब्रिगेडियर रवि कपूर को कैम्प में चलने वाली प्रशिक्षण गतिविधियों से अवगत कराया। ब्रिगेडियर रवि कपूर ने कैडेटों को दी जा रही सैन्य ड्रिल प्रशिक्षण सहित कैडेटों के लिए उपलब्ध सिमुलेटर कक्ष तथा फायरिंग ट्रेनिंग स्थल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान एनसीसी ट्रेनिंग स्टाफ द्वारा कैडेटों को मैप रीडिंग, हथियार चलाने, व्यक्तित्व विकास व कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जानकारी दी गई।

आर्ट प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार आर्यमा ने जीता

लखनऊ(यूएनएस)। सिटी मोन्टेसरी स्कूल, अलीगंज (द्वितीय कैम्पस) की कक्षा–2 की प्रतिभाशाली छात्रा आर्यमा शुक्ला ने अन्तर–विद्यालयी आर्ट प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार अर्जित कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। यह प्रतियोगिता सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट फॉर सबट्रापिकल हार्टिकल्चर के तत्वावधान में आयोजित हुई। यह जानकारी सी.एम.एस. के मुख्य जन–सम्पर्क अधिकारी हरि ओम शर्मा ने दी है। श्री शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में अनेक प्रतिष्ठित विद्यालयों के छात्रों ने प्रतिभाग किया तथापि कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच सी.एम.एस. की इस प्रतिभाशाली छात्रा ने रंग व ब्रुश के माध्यम से अपनी रचनात्मकता सोच व कलात्मक क्षमता का प्रदर्शन कर प्रथम पुरस्कार अर्जित किया। आर्यमा की बनाई कलाकृति को निर्णायक मण्डल की भरपूर सराहना मिली। प्रतियोगिता के आयोजकों ने आर्यमा को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। सी.एम.एस. संस्थापक डा. जगदीश गाँधी ने इस मेधावी छात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना की है। श्री शर्मा ने बताया कि सी.एम.एस. इस प्रकार की रचनात्मक व सृजनात्मक प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा को निखारने एवं उन्हें जीवन में आगे ही आगे बढ़ने हेतु सदैव प्रोत्साहित करता रहता है। सी.एम.एस. का लक्ष्य बच्चों को वर्ल्ड लीडर के रूप में तैयार करने वाली शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि वे कल के विश्वव्यापी समाज का नेतृत्व अपने विकसित मानवीय दृष्टिकोण से कर सके। सी.एम.एस. की इसी अनूठी शिक्षा पद्धति के फलस्वरूप विद्यालय के छात्र राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी पुरस्कार अर्जित कर विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं।

सेंटीनियल इंटर कॉलेज में हंगामे के बाद स्टूडेंट्स और टीचर्स को मिली एंट्री

लखनऊ(यूएनएस)। सेंटेनियल इंटर कॉलेज में शुक्रवार को हंगामे और जद्दोजहद के बाद आखिरकार स्टूडेंट्स और टीचर्स को प्रवेश मिल गया। डीएम के आदेश के बावजूद सेंटीनियल इंटर कॉलेज पर कब्जा करने वाले निजी स्कूल के लोग शिक्षकों और स्टूडेंट्स को प्रवेश देने के लिए तैयार नहीं थे। अफसरों की मौजूदगी में कड़ी मशक्कत के बाद ही बच्चों को एंट्री दिलाई गई। मौके पर मोर्चा संभालने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक से लेकर जिलाधिकारी तक पहुंचे। प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में प्रार्थना सभा कराई गई। फिलहाल कक्षाएं संचालित करने के लिए सेंटीनियल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को मुख्य भवन के बीच कुछ पुराने कमरे दिए गए हैं।

वैशवारा, हिन्दी साप्ताहिक
जौनपुर, सोमवार, 11 जुलाई, 2022

भूकम्प आपदा पर संयुक्त टीम नें किया मॉक अभ्यास

जौनपुर। आपदा जोखिम नियुनीकरण हेतु उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के हितधारकों के साथ कमान्डेंट मनोज कुमार शर्मा के कुशल दिशा–निर्देशन में 11 एनडीआरएफ वाराणसी की टीमें विभिन्न एजेंसियों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए संयुक्त मॉक अभ्यास का आयोजन कर रही हैं, उसी कड़ी में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय, विकास भवन में 11 एनडीआरएफ के सहायक कमांडेंट स्वराज कमल के अगुवाई में जिला प्रशासन जौनपुर एवं अन्य हितधारकों

द्वारा संयुक्त रूप से भूकंप पर एक मॉक अभ्यास आयोजित किया गया। मॉक अभ्यास के दौरान भूकंप पर एक परिदृश्य को चित्रित किया गया, जिसमें कलेक्ट्रेट कार्यालय, विकास भवन की एक इमारत ढह गई और कुछ कर्मचारी जख्मी हालत में फंस गए। तदनुसार, ई ओ सी (इमेरजेन्सी आपरेशन सेटर) को घटना के बारे में सूचित किया गया, जिसने एनडीआरएफ के नियंत्रण कक्ष एवं सभी संबंधित हितधारकों को आपात प्रतिक्रिया के लिए सूचित किया। एनडीआरएफ की टीम के पहुंचने से पहले सतही पीड़ितों को प्रथम उत्तरदाताओं ने सुरक्षित निकाल लिया। घटना स्थल पर पहुंचने पर एनडीआरएफ की टीम ने प्रारंभिक आकलन किया और एक साथ ऑपरेशन का बेस, कमांड पोस्ट, मेडिकल पोस्ट, कम्युनिकेशन पोस्ट स्थापित किए गए। आकलन के तुरंत बाद टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कटिंग उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए इमारत में क्षैतिज पहुँच बनाकर गंभीर रूप से फंसे पीड़ितों को बचाया। दूसरी मंजिल में फंसे अन्य पीड़ितों को विभिन्न रस्सी बचाव तकनीकों से बचाया गया। पीड़ितों को मेडिकल एजेंसियों द्वारा अस्पताल पूर्व उपचार देने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। यह पूरा मॉक अभ्यास इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित किया गया था और पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया। सांसद श्याम सिंह यादव , जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व रामप्रकाश, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की मौजुदगी में आयोजित किया गया तथा अन्य हितधारकों मे डीडीएमए, पुलिस, पीएसी, अग्नि शमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मीडिया कर्मियों एवं स्थानीय लोगों ने भाग लिया।

किसान सम्मान निधि के लिए ई-केवाईसी जरूरी

जौनपुर । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त का इंतजार कर रहे लाखों किसानों के लिए अहम खबर है, इस योजना के तहत सरकार ने अभी तक 11 किस्त के पैसे किसानों के खाते में भेज दिए हैं, अगली किस्त पाने के लिए योजना के लाभार्थियों को ई–केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ई–केवाईसी के लिए कृषक ऑनलाइन केंद्रों, जन सुविधा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से भी ई–केवाईसी करा सकते हैं। 31 जूलाई तक ई–केवाईसी की प्रक्रिया पूरी न कराने वाले किसानों की अगली किस्त रुक जाएगी। अपर जिला कृषि अधिकारी डा0 रमेश चंद्र यादव ने बताया कि जिले में कुल 738241 कृषको में से अभी तक कुल 491278 कृषको द्वारा ई–केवाईसी कराया गया है। किन्तु अभी तक 246963 कृषको ने अपना ई–केवाईसी नही कराया है। उन्होंने बताया कि ई–केवाईसी कराने के लिए आधार सेवा केंद्र/सीएससी केंद्र पर जाना होगा वहां से बायोमैट्रिक द्वारा ई–केवाईसी कर दिया जाएगा। उन्होंने जनपद के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थी किसानों से अपील किया है कि 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से अपना ई–केवाईसी करा लें अन्यथा अगली किस्त नहीं प्राप्त हो सकेगी।

अब एक कालेज में ही लग सकेगी शिक्षकों की डिग्री

जौनपुर । पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में एक शिक्षक की डिग्री कई जगहों पर लगने की सूचना पर विश्वविद्यालय अलर्ट हो गया है। इसको लेकर विश्वविद्यालय की तरफ से नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। अब संबद्ध कालेजों के शिक्षकों का पांच साल पर संविदा विस्तरण किया जाएगा। इससे कालेज व शिक्षक दोनों का भौतिक सत्यापन हो जाएगा। इसके साथ ही शिक्षकों की डिग्री पर एक ही महाविद्यालय में लग सकेगी। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आए दिन कई महाविद्यालयों की तरफ से जब शिक्षकों को हटाया जाता है तो वह रोते हुए पहुंचते हैं। तब पता चलता है कि इनकी कालेज से संविदा खत्म हो गई है, ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाता। वहीं मूल्यांकन के दौरान अभी कुछ दिन पहले फर्जी परीक्षक मिलने का मामला प्रकाश में आया था। पकड़े जाने पर पता चलता है कि कालेज से ही नहीं है। साथ ही उनकी डिग्री कई महाविद्यालयों में चल रही थी। इन सभी पर अंकुश लगाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से प्रत्येक संविदा शिक्षक का पांच साल पर संविदा विस्तारण कराया जाएगा। इसमें शिक्षकों व कालेज के जिम्मेदारों का विश्वविद्यालय के प्रशासनिक शिक्षक का नाम कालेज से जुड़ जाने पर हमेशा चलता रहता था। इस व्यवस्था के शुरू होने पर प्रबंधक व शिक्षक मनमानी व धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे।

आईटीआई में कैम्पस सेलेक्शन 13 को

जौनपुर । राजकीय आई0टी0आई0 सिद्दिकपुर के कैम्पस में 13 जुलाई को आईडियल जॉब प्लेसमेण्ट सर्विस औरंगाबाद महाराष्ट्र एवं पावना इण्डस्ट्रीज अलीगढ़ द्वारा कैम्पस सेलेक्शन किया जा रहा है जिसमें 10 वीं के साथ आई0टी0आई0 (सभी ट्रेड) व गैर तकनीकी अभ्यर्थी जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष हो जिसमें अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं वे अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, छायाप्रति, फोटो, आधार कार्ड व बायोडाटा बैंक पास बुक इत्यादि के साथ समय प्रातः 10 बजे राजकीय आईटीआई सिद्दीकपुर, जौनपुर के कैम्पस में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। उक्त जानकारी प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दी गयी।

आपत्ति कर सकते है 10 जुलाई तक

जौनपुर । अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय ने अवगत कराया है कि नवसृजित नगर पंचायतों (गौराबादशाहपुर, कचगांव, रामपुर) में पिछड़ी जातियों का रैपिड सर्वे कराया गया है, जिसका विवरण नगर पंचायत कार्यालय में रखा गया है। अतः सर्व साधारण से अपेक्षा है कि नगर पंचायत कार्यालय में जाकर परिवारों की सूची का परीक्षण कर ले, यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो नगर पंचायत कार्यालय में 10 जुलाई तक दर्ज करा ले, जिससे आपत्तियों का निस्तारण किया जा सके।

इस अवधि में पड़ने वाले सभी सार्वजनिक अवकाश पर भी नगर पंचायत कार्यालय खुले रहेंगे।

महंगाई भत्ते की किस्त घोषित न होने से आक्रोश

जौनपुर । सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश शाखा जौनपुर की मासिक बैठक कलेक्ट्रेट परिसर में जनपद अध्यक्ष सी बी सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए सर्व प्रथम अध्यक्ष जी ने पिछली बैठक में पारित प्रस्ताव पर की गई कार्रवाई से सदन को अवगत कराया, जिसे सदन द्वारा पुष्टि की गयी, तदोपरांत संगठन की सदस्यता को बढ़ाने हेतु सदस्यों से अपील एवं स्थानीय स्तर की समस्या देने को कहा गया। संगठन के संरक्षक आर पी पांण्डेय ने बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माह जनवरी से देय महंगाई राहत अभी तक घोषित न होने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए शीघ्र घोषित करने की मांग किया साथ ही कोविड 19 के नाम पर जनवरी 2020 से जून 21 तक रोके गया महंगाई के अवशेष को शीघ्र भुगतान करने की मांग सरकार से की गई। सदस्यों ने पेंशनर्स की समस्या पर सरकार की हीला हवाली पर रोष व्यक्त करते हुए प्रांतीय अधिवेशन के माध्यम से दिए गए 20 सूत्री मांगों को शीघ्र पूरी करने की मांग की गई है। बैठक को मुख्य रूप से संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आर पी सिंह, हीरालाल पांडेय, कामता प्रसाद गुप्ता, रमेश चंद, शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, भानु बाबू, शिव जोरराम, नंदलाल, सुक्खुराम, विक्रमाजीत यादव आदि ने सम्बोधित किया।

शासन की मंशा पर फिर रहा पानी माफिया कर रहे मनमानी

जौनपुर। पुलिस और वन विभाग कर्मियों के रहमों करमपर खुलेआम वन माफिया हरे और फलदार वृक्षों पर कहर बरपा रहे हैं जिन्हें चाह कर भी जिम्मेदार पकड़ नहीं पा रहे हैं। शासन की मंशा के अनुरूप एक तरफ कई करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनाई जा रही है तो वही अति तीव्र गति से वन और भू माफियाओं की सांठगांठ से हरे भरे फलदार पेड़ों को काटकर अवैध आरा मशीनों में खपत बढ़ाई जा रही है। एक तरफ संरक्षण तो दूसरी तरफ भक्षण को खुला बढ़ावा दिया जा रहा है। रुपयों की खातिर बिकते ईमान में हर व्यवधान का समुचित समाधान किया जा रहा है। जिस कारण बेखौफ होकर वन माफिया ट्रैक्टर और ट्राली लेकर हाली हाली हरे पेड़ों को नेस्तनाबूद और पुलिस की हिकमत अमली को नाकाम करके उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक लगे रोड पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में गौराबादशाहपुर थाना अंतर्गत निशान गांव में दिनदहाड़े वन माफिया ट्रैक्टर और अत्याधुनिक संयंत्रों से लैस होकर धड़ल्ले से आम के बगीचे को नेस्तनाबूद करते नजर आए। प्रीत टाइम्स संवाददाता ने कुंभकर्णी निद्रा में लीन अंजान जिम्मेदारों को घटनाक्रम से अवगत कराया तत्पश्चात खबर के उद्देश्य से जब जिम्मेदारों का फोन खटखटाया तो पूरी तरीके से लोगों का फोन उठ नहीं पाया। एक तरफ पर्यावरण को बढ़ावा देने की युक्ति तो दूसरी तरफ धरती को पेड़ों से मुक्ति दिलाने की अद्भुत योजना जिम्मेदार भ्रष्टाचार अधिकारियों और वन माफियाओं को मालामाल तथा पर्यावरण प्रदूषण को बेहाल करती नजर आती है।

कबीर पंथी मठ के सन्त जानलेवा हमले में गंभीर

जौनपुर । पुलिस की आरोपियों से तथा अपराधियों की जनमानस से निरंतर मुठभेड़ जारी है। बेकसूर अनायास ही हिकमत अमली के फेर में पड़कर जेल जा रहे हैं जबकि वहीं अन्य अपराध का शिकार होकर न्याय के लिए दर दर भटकते हुए झेल जा रहे हैं। मछली शहर कोतवाली के रामपुर कटाहित गांव स्थित सद्गुरु कबीर विज्ञान आश्रम में सत्संग मंडप के बगल में सोए आश्रम के ही संत ध्यान दास के पर बीती रात्रि दो बजे धारदार हथियार से हमला किया गया । जिसकी वजह से उनको गंभीर चोटें आई सिर और हाथ पर कई वार किए गए हैं । उनकी चीख–पुकार सुनकर आश्रम के मुख्य संत विमल दास के शोर मचाने पर अज्ञात हमलावर भाग गये। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल संत ध्यान दास को मछली शहर सरकारी अस्पताल पहुंचाया जहां

से गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने जौनपुर के बाद ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया । उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। मौके पर क्षेत्राधिकारी मछली शहर अतर सिंह कोतवाली मछली शहर के सीनियर सब इंस्पेक्टर रामप्रवेश कुशवाहा मय फोर्स के साथ आश्रम पर जांच में करने की कार्यवाही कर रहे हैं। घायल के पिता केशव दास उफ रणजीत सिंह अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है घायल के पिता भी इस ी आश्रम में रहते हैं यह लोग मूल रूप से फतेहपुर जिले के नारायणपुर थाना जहानाबाद के निवासी हैं । मौके पर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वायड ने पहुंचकर जांच किया है खोजी कुत्ता बगल की मंदिर पर जाकर कुछ देर रुका लेकिन कुछ निश्चित नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कहीं आश्रम पर कब्जा करने की नियत से तो नहीं हुआ है हमला अगल–बगल के लोगों का कहना है कि आश्रम का विवाद पिछले 2 सालों से विवाद चल रहा है इसके पूर्व मुख्य संत विमल दास 2019 में संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए थे 2021 में मिले कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं इनको प्रॉपर्टी के विवाद में तो नहीं गायब किया गया था पुलिस प्रॉपर्टी विवाद औरब आश्रम विवाद को जोड़कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले की तह तक जाएंगे । सीओ अतर सिंह ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर मिली है मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू की जा चुकी है जल्द ही मामले का पटाक्षेप होगा।

बन्द दुकाने खुलवाने को अफसरों से मिला आप

जौनपुर। जिला प्रशासन द्वारा शाही पुल पर दुकानों के बंद करवाने के विरोध में आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल

जिलाधिकारी व मुख्य राजस्व अधिकारी से मुलाकात किया। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण सिंह मुन्ना ने बताया कि वह व्यापारी जिनका दुकान शाही पुल पर जिला प्रशासन द्वारा बन्द कराया गया है, वे व्यापारी लोग 1962 से पुरातत्व विभाग का दुकान एलॉटमेंट करा कर व्यापार कर रहे थे, अपने परिवार वालों का रोजी–रोटी पाल रहे थे लेकिन अचानक जिला प्रशासन द्वारा दुकानों पर ताला मार कर उन व्यापारियों को बेरोजगार कर दिया है लेकिन आम आदमी पार्टी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी अमरनाथ यादव ने कहा कि हमें यह आशा है कि कल जिला प्रशासन से मिलने के बाद जिला प्रशासन द्वारा व्यापारियों के पक्ष में सही फैसला लिया जाएगा अगर ऐसा नहीं होता है आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी पूर्व जिला उपाध्यक्ष अमरनाथ यादव, एवं गुड्डू इत्यादि लोग मौजूद रहे।

शिकायत पर भी प्रधान नहीं बनवा रहे हैण्डपम्प

जौनपुर। रामपुर विकास खण्ड रामनगर क्षेत्र के सिरौली ग्राम पंचायत के आशापुर दलित बस्ती में 3 माह से खराब हैण्डपम्प कई बार शिकायत के बाद भी प्रधान ने नहीं बनवाया इसके विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। आशापुर सिरौली निवासी अरविंद कुमार सहित गांव के अन्य लोगों ने बताया कि दो–तीन महीने से हम लोगों का हैण्डपम्प पानी ही नहीं दे रहा है। इसकी शिकायत कई बार ग्राम प्रधान से की गई परंतु अभी तक प्रधान द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया गया। इससे हम लोगों के समक्ष पानी की समस्या बनी हुई है जबकि प्रधान द्वारा केवल आश्वासन ही मिलता है कि जल्द ही ठीक करा देंगे। लोगों के अनुसार तीन माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं हो सका समस्या का समाधान जिसके बाबत पूछे जाने पर ग्रामीणों ने बताया कि पानी के लिए काफी दूर जाना पड़ता है।

यात्रियों से भरी बस पलटी, चार घायल

मछलीशहर। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के परसूपुर गांव के पास गुरुवार की सुबह जौनपुर रायबरेली हाई–वे पर यात्रियों से भरी बस पलट गयी। बस में सवार यात्रियों में से चार यात्री घायल हो गये। घायलों में एक की हालत गम्भीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। बस पलटने से कई घंटों हाई–वे जाम रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन मंगाकर रास्ते में पलटी बस को किनारे कराकर रास्ता चालू कराया। जानकारी के अनुसार दिल्ली से वाराणसी चलने वाली डबल डेकर सफर एक्सप्रेस बस दिल्ली से वाराणसी के लिए दो दर्जन सवारियों को लेकर आ रही थी। सुबह बस जैसे ही परसूपुर गांव के पास पहुंचे अचानक बस अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई । बस पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गया। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर आस पास के लोग जुट गये। शीशा तोड़कर सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया।

मंत्री के निरीक्षण में कई ब्लॉक के शिक्षकों का जमघट

जौनपुर। बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री संदीप सिंह शुक्रवार को जिले में पहुँच । इस दौरान उन्होंने बाकराबाद के परिषदीय विद्यालय का निरीक्षण किया। मंत्री के निरीक्षण के दौरान सिरकोनी ब्लॉक में निरीक्षण के दौरान वहां दूसरे ब्लॉक के शिक्षक भी मौजूद रहे। विभागीय मंत्री से जब इस इस सन्दर्भ में उनसे पुछा गया तो उन्होंने बताया की इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है। अगर ऐसा है तो भविष्य में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मंत्री के आगे– पीछे शिक्षकों का समूह साथ–साथ चलता नज़र आ रहा था। अन्य ब्लॉक के शिक्षक मौजूद रहे । प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री का निरीक्षण जिले के सिरकोनी ब्लॉक के बाकराबाद विद्यालय में था। इस दौरान वहां पर शिक्षकों का जमावड़ा नज़र आया। वहां पर सिरकोनी ब्लॉक के अलावा अन्य ब्लॉक के शिक्षक भी बड़ी संख्या में मौजूद दिखे। बारे में मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि इस बात कि जानकारी उन्हें नहीं है। भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाएगा। वहीं मंत्री से मिलने को बेताब शिक्षक अपना अपना विद्यालय छोड़ कर वहां पर मौजूद दिखे। दूर दराज के विद्यालय में तैनात शिक्षक भी विद्यालय छोड़ निरीक्षण के दौरान नज़र आये। बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री ने बताया की व्यवस्था देखकर संतुष्ट हैं। बच्चों के अभिवावक के साथ सरकार भी शिक्षा को लेकर गंभीर है। सरकार द्वारा तमाम तरह के प्रयास किये जा रहे हैं। 100 दिन के अंदर 2 करोड़ के नामांकन का लक्ष्य था। इस दौरान लगभग एक करोड़ 90 लाख से अधिक नामांकन हो गया है। उन्होंने बताया की जुलाई महीने में भी स्कूल चलो अभियान निरंतर जारी रहेगा। सरकार का प्रयास है शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन व्यवस्था उपलब्ध हो सके। आने वाले समय में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं बचेगा जो शिक्षा के दायरे से छूट जाएगा। 6 महीनों के अंदर अलग अलग लक्ष्य रखा गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया की गॉव में एक भी ऐसा घर नहीं बचना चाहिए जहाँ अभियान से कोई बच्चा छूट जाए। बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यालयों को चिन्हित कर 20 हज़ार रूपए भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि परिषदीय विद्यालयों को अब स्मार्ट बनाया जाएगा। इसके लिए विद्यालयों को आधुनिक उपकरणों से लैस किय जा रहा है। विद्यालयों को इसके अलावा फर्नीचर और प्रोजेक्टर से भी लैस कराया जाएगा।

आग लगने से कई किसानों का घर राख

जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के करसावां गांव में आग लगने से कई घर, मडहे जलकर राख हो गए, घटना के बाद पहुंचे उच्च अधिकारियों ने सरकारी सूविधाओ का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया है। करसावां गावं के निवासी के महेन्द्र पाल का कच्चा मकान है आर्थिक स्थिती ठीक ना होने के कारण परिवार इसी घर मे रहने को विवस है । सुबह खाना खाने के बाद महेन्द्र घर के बाहर बैठा हुआ था। इसी बीच मडहे के उपर से धुंआ निकलने लगा जब तक महेन्द्र कुछ समझ पाता तब तक आग ने विकराल रुप धारण कर लिया और बगल में बने राजकुमार पाल के कच्चा मकान में आग लग गई लोग जब तक आग पर काबू पाते तब तक बगल में बने एक और कच्चा मकान भुलई पाल के घर में भी आग लग गई और चारो तरफ हाहाकार मच गया है। शोरगुल की आवाज सुनते ही आसपास के लोग जुट गए और आग बुझाने लगे तभी बगल में सोहन निषाद के महडे में आग की चिनगारी जाने से मडहे में रखा भुसा भी जलने लगा और देखते देखते आग की चपेट में कई घर आ गया और जलकर राख हो गया ग्रामीणो ने इसकी सुचना दमकल विभाग को दी लेकिन जब तक दमकल विभाग मौके पर पहुंचती तक ग्रामीणो ने आग पर पा लिया था। घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस और लेखपाल ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीडित परिवार को सरकारी सुविधाओ का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया है।

तेज गर्मी में बिजली कटौती कोढ़ में खाज साबित

जौनपुर। बारिश न होने से जहां गर्मी विराल रूप धारण कर लिया है ऐसी हालत में बिजली कटौती कोढ़ में खाज साबित हो रही है। चारो ओर गर्मी और बिजली की आवाजही से लोग आजि आ गये है। बारिश में देरी से खेती का काम पिछड़ रहा है। तेज धूप से धान का बेहन सूख रहा है और तैयार बेहन से धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। इससे किसान हताश दिख रहा है उसका कहना है कि बिजली न रहने से मोटर चलाकर भी धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। ग्रामीण क्षेत्रो में बिजली की धुआध ार कटौती से लोग बीमार पड़ रहे है और दृाहि दृाहि मची है। ज्ञात हो कि धान की खेती बारिश पर आश्रित है और का वर्षा जब कृषि सुखाने की कहावत चरितार्थ हो रही है। यह कहावत आलसी और भाग्य के भरोसे रहने वाले लोगों के लिए चरितार्थ होती है। वे लोग जीवन में अपने हर दुर्भाग्य को पूर्व जन्म का कर्म मानकर रोते रहते हैं। स्वयं की अनदेखी से हुई मुसीबत को भी दुर्भाग्य के मथे मड़ देते हैं। यदि समय रहते हुए कार्य किया जाए, तो कभी इस प्रकार की मुसीबत सामने नहीं आती है। जो लोग दूसरों के भरोसे रहकर अपना कार्य करते हैं, वह भी समय आने पर पछताते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने पुरूषार्थ के अतिरिक्त किसी अन्य का सहारा न ले। जो मनुष्य अपने भुजबल और ईश्वर पर विश्वास कर कार्य करते हैं कठिनाई उनके आगे नतमस्तक हो जाती है। ईश्वर ने मनुष्य को दो हाथ दिए हैं, जिनके सहारे मनुष्य चाहे, तो चट्टान को अपने रास्ते से हटाने का पौरुष रखता है। जापान सबसे छोटा द्रीप है परन्तु उसने भाग्य के भरोसे न रहकर जो सफलता पाई है वह अद्भुत है। कहा जाता है आज जापान हर क्षेत्र में अग्रणीय है। ऐसा वहाँ के लोगों के कठोर परिश्रम के कारण ही संभव हो पाया है। यदि वह अपनी समृद्धी के लिए दूसरे देशों पर ष्प्रकृति परनिर्भर रहता, तो वह आज वह इतना समृद्ध शाली नहीं होता।

सम्पदाकीय कार्यालय

वैशवारा पत्र के प्रधान संपादक रमाकान्त पाण्डेय गोपालपुरी के लिए प्रकाश एवं मुद्रक सुनील कुमार श्रीवास्तव द्वारा उमरपुर हरिवन्धनपुर नईगंज जौनपुर से प्रकाशित किया। स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सुनील कुमार श्रीवास्तव ने अरूणा प्रेस मेंहनगर आजमगढ़ से प्रकाशित किया।
सम्पादक : सुनील कुमार श्रीवास्तव
मो. 9455322393
सह सम्पादक डा. आदित्य सिंह
मो. 9415893741
जिला संवाददाता : हरिशचन्द्र यादव
मो. 8858583480
कानूनी सलाहकार (एडवोकेट) : सन्तोष कुमार श्रीवास्तव

Email:- vaashvara.123hr@gmail.com
Website:- vaashvara.com

समाचार पत्र में छपी सामग्री के लिए लेख व संवाददाता स्वयं जिम्मेदार होगा पी.आर.वी. के तहत